मुख्यमंत्री भजनलाल केन्द्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी व मनसुख मांडविया से मिले

उन्होंने केन्द्रीय मंत्रियों से खाद्य, सुरक्षा, ऊर्जा आत्मनिर्भरता, कौशल विकास व खेलों पर विस्तृत चर्चा की

नई दिल्ली/जयपुर, 2 जून। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को नई दिल्ली में केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी एवं केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया से मुलाकात की।

मुख्यमंत्री की केन्द्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से राजस्थान में खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ करने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक सशक्त बनाने तथा प्रदेश को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने हेतु नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में जारी विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं व आगामी विकास परियोजनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने राजस्थान में हरित ऊर्जा के क्षेत्र में हो रही प्रगति और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर-2 के क्रियान्वयन की सराहना की।

- **केन्द्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने राजस्थान में हरित ऊर्जा के क्षेत्र में हो रही प्रगति और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर-2 के क्रियान्वयन की सराहना की।**

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को नई दिल्ली में केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी एवं केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया से मुलाकात की।

मुख्यमंत्री की केन्द्रीय मंत्री डॉ. मांडविया से राजस्थान के युवाओं के कौशल विकास, रोजगार के नए अवसरों के सृजन और राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने व स्थानीय खिलाडियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं व प्रोत्साहन देने को लेकर सकारात्मक चर्चा हुई। साथ ही, 'माय भारत' के माध्यम से युवाओं को प्रोत्साहन देने की रूपरेखा पर भी विचार-विमर्श किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार राजस्थान के युवाओं की प्रतिभा को नई उडान देने और उनके उज्ज्वल व सुरक्षित भविष्य के लिए पूर्णत: संकल्पित और निरंतर प्रयासरत है।

द. सूडान में 550 भारतीय शांति सैनिकों को सम्मानित किया

नई दिल्ली, 02 जून। दक्षिण सूडान में यूएन मिशन (यूएनएमआइएसएस) के तहत कार्यरत 53 महिलाओं समेत 550 से अधिक भारतीय शांति सैनिकों को नागरिकों की सुरक्षा और संघर्ष प्रभावित देश में शांति निर्माण प्रयासों के प्रति उनकी निष्ठा और प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया गया है। दक्षिण सूडान के मलाकाल शहर में एक समारोह में कुल 565 भारतीय शांति सैनिकों ब्लू हेलमेट और 464 रवांडा के शांति सैनिकों को यूएन मेडल आफ ऑनर प्रदान किया गया। यूएनएमआइएसएस के अनुसार, ब्लू हेलमेट का तात्पर्य उन सैन्य कर्मियों, पुलिस अधिकारियों और नागरिक विशेषज्ञों से है जो संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक बलों के संचालनात्मक कमान के तहत कार्यरत हैं। दक्षिण सूडान में यूएन मिशन के बल कमांडर मेजर-जनरल जुनहुई वू ने कहा कि हर मेडल "हमारे बहादुर शांति सैनिकों के साहस और सहनशीलता का जश्न मनाता है, जो चुनौतीपूर्ण वातावरण में अनुशासन, संचालनात्मक प्रभावशीलता और टीमवर्क के उच्चतम मानकों को प्रदर्शित करते हैं।"

जैसलमेर में तूफान से चार सौ बिजली के पोल गिरे

जैसलमेर व सम पंचायत समिति के 150 गाँवों का जिला मुख्यालय से सम्पर्क कटा, ग्रामीण क्षेत्रों में अँधेरा छाया

जैसलमेर, 2 जून (निसं)। सीमावर्ती जिले जैसलमेर में सोमवार रात्रि को आए भीषण अंधड़, चक्रवाती तूफान और मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई। तेज गति से चलीं विनाशकारी हवाओं के कारण जोधपुर डिस्कॉम का बुनियादी ढांचा पूरी तरह ध्वस्त हो गया, जिसके चलते जिले भर में चार सौ से अधिक बिजली के खंभे जमीन पर आ गिरे। तूफान का सबसे ज्यादा असर काठोडी जीएसएस सम और भारत-पाक सीमा से सटे ग्रामीण इलाकों में देखने को मिला।

तेज अंधड़ के कारण बिजली की लाइनें और तार टूटने से जैसलमेर तथा सम पंचायत समिति के करीब 150 से अधिक गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। इन ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले 16 घंटों से पूरी तरह अंधेरा छाया हुआ है। और आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। वहीं नलकूप और वाटर पंप बंद होने से सीमावर्ती गांवों में पीने के पानी का गंभीर संकट भी खड़ा हो गया है। अंधड़ की विभीषिका के बाद जोधपुर डिस्कॉम की तकनीकी टीमें और अधिकारी फील्ड में उतरे। मुख्य फीडरों को दुरुस्त करने और गिरे हुए खंभों को हटाने का काम युद्धस्तर पर किया जा रहा है। डिस्कॉम सूत्रों के अनुसार, शुरुआती आंकलन में ही विभाग को भारी आर्थिक नुकसान सामने आया है और दूरदराज की ढाणियों व अंचलों से रिपोर्ट आने के बाद नुकसान का यह आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है।

- **तूफान की रफ्तार इतनी तेज थी कि बिजली के खंभों के साथ कई बड़े पेड़ उखड़ गए, रिसॉर्ट्स की दीवारें ढह गईं, घरों के टीन शैड व होर्डिंग्स हवा में उड़ गए।**

डिस्कॉम अधिकारियों का कहना है कि प्रमुख कस्बों और आवश्यक सेवाओं वाले क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति जल्द बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अंदरूनी ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवस्था पूरी तरह सामान्य होने में 1 से 2 दिन का समय लग सकता है।

सिद्धारमैया 2028 ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

होगा, क्योंकि वे बेंगलुरु में यातायात संबंधी समस्याओं से बचना चाहते हैं।

उन्होंने कहा, हमने बेंगलुरु में अव्यवस्था से बचने के लिए लोक भवन में सादगीपूर्ण शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करने का निर्णय लिया है। हमें आम लोगों की सुविधा का भी ध्यान रखना है। उन्होंने आगे कहा, चूंकि यह कार्यदिवस है, इसलिए हम बेंगलुरु शहर में किसी तरह की अव्यवस्था नहीं चाहते। पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को राजधानी लाने के लिए 17,000 से अधिक वाहनों की बुकिंग पहले ही की जा चुकी है। पुलिस अधिकारी यातायात बाधित होने और जनता की परेशानियों को लेकर चिंतित थे।

भाजपा में भी छाया ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सक्रिय हैं, जो उनके पिता का निर्वाचन क्षेत्र है। बरेली में, वरिष्ठ भाजपा नेता और झारखंड के पूर्व राज्यपाल संतोष गंगवार की पुत्री श्रुति अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश में हैं। पूर्व भाजपा सांसद बृज भूषण शरण सिंह पहले ही एक पुत्र के लिए यूपी विधानसभा और एक अन्य के लिए लोकसभा में स्थान सुरक्षित कर चुके हैं। अब वे नोएडा से अपनी पुत्री शालिनी की राजनीतिक शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन यह आसान नहीं होगा, क्योंकि नोएडा का प्रतिनिधित्व राजनाथ सिंह के बडे पुत्र पंकज करते हैं। सूची में अन्य लोग हैं- यूपी की पूर्व मंत्री रीता बहुगुणा जोशी के पुत्र मयंक जोशी, जो कथित तौर पर लखनऊ छावनी से भाजपा टिकट पाने के प्रयास में हैं। दिलचस्प बात यह है कि मयंक ने पिछले विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी जॉइन की थी और अभी तक उस पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है। सूत्रों के अनुसार, मयंक, जो पार्टी टिकट दे देगी, उसी से चुनाव लड़ेंगे। अमेठी में, पूर्व सांसद संजय सिंह की पुत्री आकांक्षा ने भी मैदान में टिकट के लिए अपनी दावेदारी पेश की है।

शादीशुदा पुत्रियों को अनुकंपा नियुक्ति से बाहर नहीं किया जा सकता

नई दिल्ली, 02 जून। उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि शादीशुदा बेटियों को अनुकंपा नियुक्ति से बाहर नहीं किया जा सकता है और परिवार की परिभाषा से उन्हें हटाना साफ तौर पर मनमाना और संवैधानिक रुप से गलत है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा की अध्यक्षता वाली बेंच ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को निरस्त करते हुए ये टिप्पणी की।

दरअसल, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा था कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए परिवार की परिभाषा में शादीशुदा बेटी शामिल नहीं है। इस आधार पर उच्च न्यायालय ने अनुकंपा के आधार पर उसे उचित मूल्य की दुकान का डीलर नियुक्त करने की उसकी मांग को खारिज कर दिया था। महिला ने यूपी सरकार के 2019 के एक आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें शादीशुदा बेटियों को परिवार की परिभाषा से बाहर रखा गया था। इस फैसले को एक महिला ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जिस नियम को चुनौती दी गई है, वह इस सोच पर आधारित है कि शादी के बाद बेटी अपने माता-पिता के परिवार की सदस्य नहीं रहती या उन पर निर्भर नहीं रहती। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ऐसी सोच संवैधानिक रुप से गलत है।

ममता के धरने में केवल 7 विधायक, 2 सांसद पहुंचे

कोलकाता, 02 जून। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी द्वारा मंगलवार को कोलकाता के धर्मतल्ला स्थित वाई चैनल पर आयोजित धरना कार्यक्रम में पार्टी के सीमित जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है। हालिया विधानसभा चुनाव में सत्ता गंवाने के बाद, भाजपा सरकार के खिलाफ आयोजित इस विरोध-प्रदर्शन में तृणमूल के केवल सात विधायक और दो सांसद ही शामिल हुए।

धरना कार्यक्रम में मौजूद विधायकों में चंद्रिमा भट्टाचार्य, सोवनदेब चट्टोपाध्याय, नायना बंद्योपाध्याय, मदन मित्रा, अशोक देब, असीमा पात्रा और बिमान बनर्जी शामिल थे। वहीं सांसदों में डोला सेन और कल्याण बनर्जी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

तृणमूल कांग्रेस के पास हालिया चुनाव के बाद भी बड़ी संख्या में निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं।

सुप्रीम कोर्ट के 5 ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हैं। जस्टिस शील नागू पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट (मूल एचसी : मध्य प्रदेश) के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे, जस्टिस श्री चंद्रशेखर बॉम्बे हाई कोर्ट (मूल एचसी: झारखंड) के मुख्य न्यायाधीश के रूप में, जस्टिस संजीव सचदेवा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (मूल एचसी: दिल्ली) के मुख्य न्यायाधीश के रूप में, और जस्टिस अरुण पल्ली जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट (मूल एचसी: पंजाब और हरियाणा) के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे।

पांचवीं नियुक्त जज, सीनियर एडवोकेट वी. मोहना, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करती थीं और उन चुनिंदा वकीलों में से एक बन गई हैं, जिन्हें सीधे सुप्रीम कोर्ट की बेंच में पदोन्नत किया गया है।

बंदी की मौत पर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कोर्ट ने आईओ से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी थी। आईओ ने 25 मई की रिपोर्ट में कहा कि मौजूदा मामले में अनुसंधान जारी है। इस पर कोर्ट ने रिपोर्ट पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जब एक बार पूर्व में अनुसंधान पूरा होकर जुर्म प्रमाणित मान लिया गया है तो फिर अब आरोपियों के खिलाफ अनुसंधान लंबित होना क्यों बताया जा रहा है। गौरतलब है कि इस मामले की न्यायिक जांच में बंदी की मौत का जिम्मेदार कांस्टेबल इकबाल खां, कांस्टेबल राजूराम और धर्मी मीणा को बताया है। वहीं परिवादी पक्ष के व्यक्ति शिवलाल, बाबूलाल और निजी वाहन चालक नदीम के साथ आपराधिक षड्यंत्र करने की बात कही है।

टीएमसी में नेतृत्व के खिलाफ ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पार्टी कार्यालयों से बरामद वस्तुओं की सूची दिन-ब-दिन और भी अधिक चौंकाने वाली होती जा रही है। राज्य के कालना क्षेत्र में एक पूर्व विधायक ने एक आलीशान महल जैसा घर बना रखा था, जहां से एक एम्बुलेंस भी बरामद हुई है।

छात्र नेताओं के कब्जे वाले कॉलेज यूनियन के कुछ कमरों से भी बड़ी मात्रा में नकदी मिलने की खबरें सामने आ रही हैं। मध्य कोलकाता के सुरेन्द्रनाथ कॉलेज के छात्र संघ कक्ष से भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई। कॉलेज छात्र नेता देबाशीष बनर्जी (जिसे "कान-काटा देबू" के नाम से जाना जाता था) पूरे कॉलेज के मामलों को नियंत्रित करता था, यहाँ तक कि स्थानीय विधायक तक का यूनियन के मामलों पर कोई प्रभाव नहीं था। बताया जाता है कि कॉलेज यूनियन हर साल दाखिला घोटालों से करोड़ों रुपये कमाती थी। कहा जाता है कि यह पैसा तृणमूल के शीर्ष नेताओं तक पहुंचता था। बताया जाता है कि कान-काटा देबू के सुदीप बंद्योपाध्याय और उनकी पत्नी से करीबी संबंध थे। यूनियन कक्ष में दो लगेज ट्रॉली मिलीं, जिनमें करैंसी नोटों के बड़े-बड़े बंडल भरे हुए थे। इनमें से काफी नोटों को दीमक खा चुकी थी। ट्रॉलियों से 500 रुपये के नोट और पुराने बड़ी कीमत वाले करैंसी नोट बरामद हुए। राज्य पुलिस ने पूरी बरामदगी को अपने कब्जे में ले लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि कल इन करैंसी नोटों की जांच करेंगे और उनके बारे में निर्णय लेंगे। कई नोट इतने खराब हो चुके हैं कि उनका इस्तेमाल करना संभव नहीं है। इन कार्यालयों में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की तस्वीरें लगी हुई थीं। कॉलेज यूनियन के कमरे से सटे हुए दो बैडरूम भी थे। कमरा वातानुकूलित था और उसमें व्यवस्थित बिस्तर, तौलिये तथा अन्य सुविधाएं मौजूद थीं। यह कमरा होटल के कमरे की तरह भी इस्तेमाल किया जाता था, जिसे किराये पर दिया जा सकता था। इसके साथ एक संलग्न स्नानघर भी था। कमरे में फ्रिज भी रखा हुआ था। कमरे में पेय पदार्थों की बोतलें भी मिली हैं। चुनाव परिणाम घोषित होने के एक महीने के भीतर ही पूरे बंगाल की स्थिति बेहद असामान्य होती जा रही है। लोग गुस्से में सड़कों पर उतर रहे हैं और तृणमूल कांग्रेस के विभिन्न स्तरों के प्रतिनिधियों पर हमले कर रहे हैं। दूसरी ओर, कई प्रसिद्ध गायक और अभिनेता भी शिकायत कर रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस ने गायकों पर अपना शिकंजा कस रखा है, जिससे उन्हें काम पाने की आज़ादी नहीं मिल पा रही है।

पेपर लीक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

यादव की ओर से पेश वकील अंबिका ने कहा कि उसे नीट परीक्षा की तैयारी करनी है। उसने 03 मई को नीट की परीक्षा दी थी जो निरस्त हो गई थी।

लोखंडे ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

को सौंपा गया है। उन्हें एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी होगी। इस बीच, केंद्र सरकार ने वरिष्ठ आईएएस लोखंडे प्रशांत सीताराम को सीबीएसई का नया चेयरमैन और इंडियन इंफोर्मेशन सर्विस के अधिकारी वरुण भारद्वाज को सचिव नियुक्त किया है।

'मैं नहीं होता तो तुम जेल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हमले नहीं रोकता है तो इज़रायल बेरुत में "आतंकवादी लक्ष्यों" को निशाना बनाएगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने हिज़बुल्लाह नेतृत्व के प्रतिनिधियों से भी बातचीत की, जिन्होंने इज़रायल पर हमले रोकने पर सहमति जताई।

ट्रंप ने कहा, "मैंने हिज़बुल्लाह के नेताओं के प्रतिनिधियों से भी बातचीत की, और उन्होंने इज़रायल और उसके सैनिकों पर गोलीबारी रोकने पर सहमति दी। इसी तरह, इज़रायल ने भी उनके खिलाफ गोलीबारी रोकने पर सहमति दी। देखते हैं यह कितने समय तक चलता है, उम्मीद है कि यह हमेशा चलेगा।"

इस बीच, एक्सियोस ने बताया कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच तीखी बातचीत हुई।

एक्सियोस ने एक अनाम अमेरिकी अधिकारी के हवाले से बताया कि ट्रंप ने कहा, "तुम एकदम पागल हों। अगर मैं नहीं होता तो तुम जेल में होते, मैं तुमको बचा रहा हूँ। अब हर कोई तुमसे नफ़रत करता है और इस कारण हर कोई इज़रायल से नफ़रत करता है।"

दूसरे स्रोत ने एक्सियोस को बताया कि ट्रंप बहुत गुस्से में थे और एक समय नेतन्याहू पर चिल्लाते हुए बोले, "तुम क्या कर रहे हो?" एक अन्य अधिकारी ने कहा कि इस कॉल के दौरान ट्रंप ने नेतन्याहू को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया।

अज्ञात अधिकारी के अनुसार, नेतन्याहू ने कहा, "ठीक है, ठीक है, बस सुनिश्चित करो कि सब संभल जाए।"

ट्रंप का हस्तक्षेप ईरान के साथ कूटनीतिक प्रयासों पर अनिश्चितता के बीच आया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि तेहरान के साथ वार्ता जारी है, भले ही हालिया गोलाबारी ने लगभग दो महीने के युद्धविराम को बार-बार परखा हो। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर कहा, "इस्लामिक गणराज्य ईरान के साथ वार्ता तेजी से जारी है।"

ईरान और अमेरिका के बीच युद्धविराम लगातार हमलों और जवाबी हमलों से तनाव में है, जबकि दोनों पक्ष समझौते के माध्यम से संघर्ष समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि दोनों देश समझौते के कितने निकट है और आगे की सैन्य कार्रवाई वार्ता को प्रभावित कर सकती है।

इससे पहले, ट्रंप ने एनबीसी न्यूज़ को बताया कि उन्हें ईरान के वार्ता स्थगन के फैसले की पूर्व सूचना नहीं दी गई, लेकिन उन्होंने इस बात को तूल नहीं दिया। उन्होंने कहा, "अगर वे बात करना बंद कर दें तो ठीक है। यह कहने के लिए उचित है, क्योंकि वे लड़ाके ज्यादा अच्छे नहीं है, पर बेहतर वार्ताकार हैं।"

ट्रंप ने कहा, "लेकिन उन्होंने हमें इसकी सूचना नहीं दी। इसका मतलब यह नहीं कि हम वहाँ जाकर बम गिराने लगेंगे।"

अमेरिकी सेना और ईरान ने सप्ताहांत और सोमवार को एक दूसरे पर हमले और जवाबी हमले किए, जिससे लगभग दो महीने पुराने युद्धविराम को खतरा पैदा हुआ।

युद्धविराम के बावजूद, इज़रायल ने लेबनान में अपनी सैन्य कार्रवाई जारी रखी, और अपने 26 साल के सबसे गहरे आक्रमण को अंजाम दिया।

सोमवार को नेतन्याहू ने हिज़बुल्लाह के नियंत्रण वाले बेरुत के दक्षिणी उपनगरों पर हमले का आदेश दिया, जिससे संघर्ष और बढ़ने का संकेत मिला। इसके तुरंत बाद ट्रंप ने इज़रायली नेता को फोन किया।

तेहरान और वॉशिंगटन के बीच जारी वार्ता से ईरान द्वारा हटने की घोषणा के बाद, ट्रंप कथित रूप से इज़रायल पर भड़क गए।

अब यह देखना बाकी है कि क्या ट्रंप का यह गुस्सा अमेरिकी जनता को दिखाने के लिए एक चालाक मीडिया कवायद थी कि सब कुछ ट्रंप के काबू में है, या वास्तव में नेतन्याहू को काबू में करने का प्रयास था।

भारत में ब्लू कॉलर वर्कर्स (नलवाला, बिजली वाला ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कई देशों में ऐतिहासिक रूप से कम बेरोजगारी दर होने के बावजूद, निर्माण श्रमिक, मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, देखभाल कर्मचारी (केयर गिवर्स) और लॉजिस्टिक्स श्रमिकों को ढूंढना कठिन होता जा रहा है। उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों में व्यापारिक सर्वेक्षणों और नीतिगत दस्तावेजों में अब स्पष्ट रूप से "कुशल तकनीकी व्यवसायों की कमी" का उल्लेख किया जा रहा है। प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर और एचवीएसी तकनीशियन उन पदों में शामिल हैं, जिन्हें भरना सबसे कठिन माना जा रहा है, क्योंकि पुराने कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पर्याप्त संख्या में युवा इन क्षेत्रों में नहीं आ रहे हैं।

यूरोपीय संघ में 2023 के दौरान लगभग तीन-चौथाई कंपनियों ने कहा कि उन्हें सही कौशल वाले कर्मचारी नहीं मिल रहे हैं। यह संख्या पांच वर्ष पहले की तुलना में लगभग दोगुनी है।

जर्मनी में श्रम बाजार के आंकड़ों से पता चलता है कि 2024 में 80 प्रतिशत से अधिक नियोक्ताओं ने भर्ती में कठिनाइयों की शिकायत की। इससे स्पष्ट है कि यूरोप की औद्योगिक अर्थव्यवस्था में श्रम बाजार कितना तंग हो चुका है।

इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक और अन्य कुशल तकनीकी कर्मचारी इस महाद्वीप में सबसे अधिक कमी वाले पेशों में गिने जाते हैं। यूरोपीय श्रम प्राधिकरण भी इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर और मैकेनिक को सबसे अधिक कमी वाले व्यवसायों में गिनता है। अमेरिका में भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। सरकारी और उद्योग संबंधी अनुमानों के अनुसार, अगले कुछ वर्षों में वहां लाखों नहीं, बल्कि सैकड़ों हजार प्लंबरों की कमी हो सकती है। साथ ही अगले दशक में इलेक्ट्रिशियन और रखरखाव कर्मचारियों की मांग पूरे रोजगार बाजार की औसत वृद्धि से अधिक रहने की संभावना है।

जैन का मानना है कि इस प्रवृत्ति को जनसांख्यिकीय बदलाव और तेज कर रहे हैं। उनका कहना है कि अब दुनिया की आधे से अधिक आबादी ऐसे समाजों में रहती है जहां आबादी बूढ़ी हो रही है और जन्म दर कम है। इससे उच्च आय वाले देशों को ब्लू-कॉलर कर्मचारियों के लिए विदेशों की ओर देखना पड़ रहा है।

जनसांख्यिकी विशेषज्ञ इस स्थिति को अधिक संतुलित शब्दों में बताते हैं। उनके अनुसार, विकसित देशों में कामकाजी उम्र की आबादी घट रही है और बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है, जिससे सामाजिक सुरक्षा और देखभाल व्यवस्था पर दबाव बढ़ेगा, जब तक कि उत्पादकता न बढ़े, सेवानिवृत्ति की आयु न बढ़ाई जाए या प्रवास में वृद्धि न हो।

जैन ने कहा, "उच्च आय वाले देश जनसांख्यिकीय पतन का सामना कर रहे हैं और भारतीय ब्लू-कॉलर श्रमिक इसका समाधान हैं।" हालांकि "पतन" शब्द का प्रयोग उन्होंने स्वयं किया है, लेकिन जिन अंतर्निहित दबावों की वे बात कर रहे हैं, वे आधिकारिक अनुमानों में भी दिखाई देते हैं। उनका यह भी कहना है कि आप्रवासन (इमिग्रेशन) को लेकर राजनीतिक सोच बदल रही है। अमीर देशों को अभी भी श्रमिकों की जरूरत है, लेकिन कई पश्चिमी देशों में व्यापक आप्रवासन के प्रति जनसमर्थन कम हुआ है। परिणामस्वरूप सरकारें वीज़ा नियमों को कड़ा कर रही हैं, जबकि उद्योग संगठन निर्माण, कृषि और बुजुर्गों की देखभाल जैसे क्षेत्रों के लिए अधिक विदेशी श्रमिकों की मांग कर रहे हैं।

हाल के वर्षों में आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) जैसे संस्थानों के आंकड़ों से पता चलता है कि कुछ विकसित देशों में काम से जुड़े प्रवास (माइग्रेशन) में कमी आई है, क्योंकि वीज़ा नियम सख्त हुए हैं और इनका राजनीतिक विरोध बढ़ा है, हालांकि कुल प्रवासी आबादी अभी भी ऐतिहासिक मानकों के हिसाब से ऊंची बनी हुई है। जैन ने लिखा, "बिना नियंत्रण वाले आप्रवासन के प्रति पश्चिम का आकर्षण समाप्त हो रहा है, क्योंकि कुछ प्रवासी स्थानीय समाज में घुल-मिल नहीं पाते और संस्कृति को ही बदलना चाहते हैं।" उनका मानना है कि सरकारें श्रम की कमी को पूरा करने पर केन्द्रित आर्थिक प्रवास कार्यक्रमों को प्राथमिकता दे सकती हैं, जिनका उद्देश्य केवल श्रमिकों की कमी वाले क्षेत्रों को भरना हो।

पश्चिमी यूरोप में प्रवासियों के एकीकरण पर हुए शोध भी इस चिंता के कुछ हिस्सों का समर्थन करते हैं। दीर्घकालिक अध्ययनों में पाया गया है कि कुछ प्रवासी समूहों को रोजगार, शिक्षा और सामाजिक अवसरों में स्थानीय लोगों की तुलना में लगातार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और कमजोर या अपर्याप्त नीतियों के कारण उनका समाज में समावेशन धीमा और राजनीतिक रूप से विवादास्पद बना रहता है।

इससे भारत कुशल तकनीकी कर्मचारियों के लिए वैश्विक प्रतिस्पर्धा का केन्द्र बन सकता है।

अपनी बड़ी और अपेक्षाकृत युवा आबादी तथा खाड़ी देशों, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के साथ लंबे समय से बने प्रवासन संबंधों के कारण भारत पहले से ही नर्सों, देखभाल कर्मचारियों (केयर गिवर्स) और निर्माण श्रमिकों का एक प्रमुख स्रोत है। इन देशों के नीति-निर्माता श्रमिकों की कमी वाले क्षेत्रों के लिए विदेशी कर्मचारियों को आकर्षित करने की नई योजनाओं पर विचार कर रहे हैं। इनमें देखभाल कर्मचारियों के लिए त्वरित वीज़ा और इलेक्ट्रिशियन जैसे तकनीकी व्यवसायों के लिए विशेष कार्यक्रम शामिल हैं। लेकिन विडंबना यह है कि भारत शायद वही कार्यबल तैयार कर रहा है, जिसकी वैश्विक बाजार को सबसे कम आवश्यकता है।

जहां विदेशों में ब्लू-कॉलर श्रमिकों की मांग बढ़ रही है, वहीं भारत लाखों ऐसे डिग्रीधारी युवाओं को तैयार कर रहा है, जो पहले से ही भीड़भाड़ वाले वाइट-कॉलर रोजगार बाजार में प्रवेश कर रहे हैं। हाल के अध्ययनों और श्रम सर्वेक्षणों के अनुसार, युवा स्नातकों में बेरोजगारी दर लगभग 40 प्रतिशत के आसपास बनी हुई है, जो कम शिक्षित युवाओं की तुलना में काफी अधिक है। दूसरी ओर, एम्प्लॉयर, प्रैक्टिकल एवं स्किल बेस्ड भूमिकाओं के लिए लोगों की कमी की शिकायत कर रहे हैं।

शोधकर्ताओं का अनुमान है कि श्रम बाजार में प्रवेश करने वाले स्नातकों में से केवल लगभग हर चौदहवां व्यक्ति ही पहले वर्ष में स्थायी वेतन वाली नौकरी हासिल कर पाता है। यह बात शिक्षा से जुड़ी उम्मीदों और उपलब्ध काम के ढांचे के बीच के अंतर को उजागर करती है। साथ ही, विभिन्न परामर्श संस्थाओं और नीति संगठनों के अनुमान बताते हैं कि अगले दशक में भारत को जिन नई नौकरियों की आवश्यकता होगी, उनमें बड़ी संख्या लॉजिस्टिक्स, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और बुनियादी सेवाओं जैसे क्षेत्रों की ब्लू-कॉलर नौकरियाँ होंगी। इसके अलावा, देश में विशाल वर्कफोर्स होने के बावजूद, सही तकनीकी कौशल वाले कर्मचारियों की कमी पहले से ही बनी हुई है। भारत के श्रम बाजार पर हुए अध्ययनों में यह भी बताया गया है कि कई ब्लू-कॉलर नौकरियां अभी भी असंगठित, कम वेतन वाली और असुरक्षित हैं। यही कारण है कि नई पीढ़ी इन व्यवसायों की ओर आकर्षित नहीं होती और कुशल तकनीकी कर्मचारियों की कमी और बढ़ जाती है।

जैन के अनुसार, एक गंभीर असंतुलन पैदा हो रहा है।

उन्होंने लिखा, "मेरा मानना है कि अगले पांच वर्षों में भारत में प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, बढ़ई, ड्राइवर, नर्स और देखभाल कर्मचारियों की कमी हो जाएगी, क्योंकि वे उच्च आय वाले देशों में चले जाएंगे।"

पेपर लीक और नकल माफिया पर पुलिस का शिकंजा कसा

रीट, शिक्षक भर्ती और पटवारी भर्ती में पेपर लीक धांधली और फर्ज़ीवाड़े के फरार आरोपियों पर 10-10 हजार का इनाम घोषित

जयपुर, 2 जून। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल माफिया के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत, स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप (एसओजी) ने बडी कार्रवाई करते हुए 15 फरार आरोपियों पर दस-दस हजार रुपए का नकद इनाम घोषित किया है। ये सभी आरोपी रीट, शिक्षक भर्ती और पटवारी भर्ती जैसी महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली, पेपर लीक और फर्जीवाडे के मामलों में वांछित हैं तथा लंबे समय से अपनी पहचान छिपाकर गिरफ्तारी से बच रहे हैं।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (एसओजी) विशाल बंसल ने बताया कि इन सभी आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 419, 420, 467, 468, 471 एवं 120-बी के साथ ही राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम तथा सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) एक्ट की विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है, लेकिन फरार होने के कारण अब प्रत्येक पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है।

- **एसओजी की जाँच के अनुसार, रीट, शिक्षक भर्ती और पटवारी भर्ती में लिप्त 15 आरोपी अभी भी फरार हैं।**

एसओजी द्वारा जारी सूची में कई ऐसे आरोपी शामिल हैं, जो सरकारी सेवा या शिक्षा क्षेत्र से जुडे रहे हैं। इनमें सीकर जिले की अजीतगढ़ पंचायत समिति में कार्यरत सहायक लेखाधिकारी नागेश कुमार यादव प्रमुख हैं। इसके अलावा, शाहपुरा क्षेत्र में संचालित एमएडी फाउंडेशन कोचिंग सेंटर के संचालक दिनेश किलका भी वांछित आरोपियों में शामिल हैं।

एसओजी ने जिन आरोपियों पर दस-दस हजार रुपए का इनाम घोषित किया है, उनमें श्रीमाधोपुर (सीकर) निवासी नागेश कुमार यादव, सांचौर निवासी संगीता विश्नोई, तारपुरा (सीकर) निवासी विकास खेदर, निवाडी (सवाई माधोपुर) निवासी रामावतार मीणा, दांतारामगढ़ (सीकर) निवासी एवं कोचिंग संचालक दिनेश किलका, नागौर निवासी मनीष दाधीच, कोटपूतली निवासी भवानी शर्मा, जयपुर निवासी देवेन्द्र कुमार सैनी, जालौर निवासी कमलेश कुमार खिलेरी, बीकानेर निवासी रेवती विश्नोई, सवाई माधोपुर निवासी राजमोहन मीणा, जयपुर निवासी रविन्द्र सैनी, चोमू (जयपुर) निवासी सुभाष मुवाल, जालौर निवासी दिनेश कुमार तथा सांकड (जालौर) निवासी श्रवण कुमार शामिल हैं।

एसओजी ने आमजन से अपील की है कि यदि किसी व्यक्ति को इन फरार आरोपियों के संबंध में कोई सूचना प्राप्त हो तो वह नजदीकी पुलिस थाना या एसओजी से संपर्क कर जानकारी दे सकता है। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908